तत्काल निर्गम हेतु

विश्व बैंक

संपर्कः दिल्ली मेंः सदीप मजूमदार (91 11) 2461-7241
ईमेलः smozumder@worldbank.org

विश्व बैंक की विकास नीति संबंधी रिपोर्ट 2006 में 'सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही की व्यवस्थाओं ' के सुदृढ़ीकरण का आह्वान किया गया है

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2006ः आज नई दिल्ली में भारत की विकास नीति की समीक्षा (डीपीआर) 2006 हेतु विश्व बैंक ने अपनी अग्रणी रिपोर्ट 'सर्वसम्मिलित विकास और सेवा डिलीवरीः भारत की सफलता के आधार पर आगे बढ़ना' के नाम से जारी की है।

इस रिपोर्ट में भारत के तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं जैसे भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जल आपूर्ति की डिलीवरी में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के सांस्थानिक सुधारों, जो जवाबदेही की प्रभावी व्यवस्थाओं का सृजन करें, के माध्यम से किया गया खर्च ही सार्थक है। इस रिपोर्ट में भारत के सतत आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाओं का विशेष उल्लेख किया गया है और इस आर्थिक विकास के लाभ अधिक व्यापक बनाते हुए इस तीव्र आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए प्राथमिकता वाले उपायों को रेखांकित किया गया है।

डीपीआर 2006 में उल्लेख किया गया है कि हालांकि भारत अनेक मोर्चों पर यथा शुद्ध गरीबी को आधे से अधिक कम करने, निराक्षरता को अत्यधिक कम करने और समग्र स्वास्थ्य स्थितियों में व्यापक सुधार करने में सफल रहा है, फिर भी इन उपलब्धियों ने इस देश के लिए नई चुनौतियों को जन्म दिया है।

भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर श्री माइकल कार्टर शब्दों में,"हमारी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से यह चर्चा और आगे बढ़ेगी कि भारत की प्रमुख विकास चुनौतियां क्या हैं, जैसा कि हमारा विश्वास हैः भारत की उभरती हुई आर्थिक सफलता के आधार पर किस तरह आगे बढ़ा जाए, इसे किस तरह इस देश के 30 करोड़ नागरिकों के लिए सर्वसम्मिलित बनाया जाए जो अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करते हैं, और आम नागरिक के लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक व्यय की कारगरता में किस तरह सुधार किया जाए।"

दक्षिण एशियया के लिए सामाजिक विकास एकक की अग्रणी सामाजिक–अर्थशास्त्री और इस रिपोर्ट की एक अग्रणी लेखक लैंट प्रिटचेट ने टिप्पणी करते हुए उल्लेख किया कि, "भारत को जल और बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवहन जैसी प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए जवाबदेही की व्यवस्थाओं का अवश्य सुदृढ़ीकरण करना होगा। और यह केवल सांस्थानिक सुधारों के माध्यम से ही संभव है।"

डीपीआर 2006 में सुधार के ऐसे चार मार्गों का सुझाव दिया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही की प्रभावी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकते हैं यथा सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों का आंतरिक सुधार; नागरिकों के लिए नियमित एवं विश्वसनीय सूचना का सृजन; स्थानीय सरकारों का सुदृढ़ीकरण एवं उत्तरदायित्वों का विकेंद्रीकरण; और गैर–सरकारी प्रदाताओं की भूमिका में विस्तार। बहरहाल, इसमें सजग किया गया है कि केवल नियोजित सुधार ही वांछित बदलाव नहीं ला सकते हैं – अंततः क्रियान्वयन ही सब कुछ है।

भारत को तीव्र आर्थिक विकास के अपने पथ पर बने रहने और इस आर्थिक विकास का क्षेत्रों, इलाकों एवं लोगों तक विस्तार करने के लिए इस रिपोर्ट में निम्नलिखित का सुझाव दिया गया है:

- खराब अवसंरचना और उच्च वित्तीय घाटे की प्रमुख बाध्यकारी तंगियों को दूर करना

- समकारक त्वरकों पर ध्यान केंद्रित करना: ऐसे सुधार जो आर्थिक कुशलता में सुधार करें और आर्थिक विकास के लाभों को फैलाएं जैसे नौकरियों का सृजन करने के लिए श्रम विनियमों में बदलाव और वित्त क्षेत्र में सुधार

- प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में निवेश पर वापस लौट कर कृषि उपज को बढ़ाना

- विनियमन बोझ को कम करके, कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करके, तथा संपर्क बढ़ाने के लिए ग्रामीण अवसंरचना का विस्तार करके पिछड़े राज्यों एवं क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास हेतु माहौल में सुधार करना

- ऐसी अग्रसक्रिय नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों का सशक्तीकरण जो निष्पक्ष एवं साम्यिक शर्तों पर बाज़ार में भागीदारी करने में उनकी मदद करें

डीपीआर ऐसे प्रमुख विश्लेषणात्मक साधनों या माध्यमों में से एक है जिनके द्वारा विश्व बैंक अपने सहयोगी देशों को उनकी प्रमुख विकास चुनौतियों के लिए तैयारी करने में मदद करना चाहता है।

****

कृपया इस रिपोर्ट और भारत में विश्व बैंक के कार्यों की अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें:
http://www.worldbank.org/in